

सुबह, अपर सावि, उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
निदेशक,
समाज कल्याण,
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: ५२ वरी: ०1 / 2007
विषय:-प्रदेश में संघालित मदरसों/मकतबों को आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत लिए जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-2193/स0क0/मदरसा आधु0वे0अनु0प्रस्ताव/2006-07, दिनांक 19 सितम्बर 2006 तथा पत्रांक संख्या: 2368/स0क0/मदरसा आधु0वे0अनु0प्रस्ताव/2006-07, दिनांक 28 सितम्बर 2006 द्वारा प्रेषित मदरसों के आधुनिकीकरण प्रस्तावों पर संयुक्त विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक में प्राविद्यालय व्यवस्थानुसार निम्नलिखित 02 मदरसों में (दो अस्थापक प्राथमिक स्तर पर तथा एक अस्थापक जूनियर स्तर पर) आधुनिक विषय हेतु अस्थापक के वेतन भुगतान तथा बृक बँक की स्थापना हेतु कुल रु. 1,34,000/- (रुपये एक लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की सहित स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्रमांक	मदरसे का नाम	अस्थापकों की संख्या
01	मदरसा मकतब इस्लामिया इमदती गढ़मौरपुर, हरिद्वार	01 (प्राथमिक स्तर)
02	मदरसा कालिमा जैहरा, इस्लामनगर, खटीमा, उधमसिंहनगर	01 (प्राथमिक स्तर) 01 (जूनियर स्तर)

1- विज्ञान, गणित, अंग्रेजी/सामाजिक अध्ययन व हिन्दी विषयों के शिक्षण हेतु पूर्णकालिक शिक्षण कार्य के लिए प्राथमिक शिक्षक को रु. 3000/- (रु. तीन हजार) तथा जूनियर शिक्षक को रु. 4000/- (रुपये चार हजार) मात्र प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा नियुक्त अस्थापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट (संघलित विषय) से कम नहीं होगी अन्यथा शासन द्वारा प्रदान की जा रही स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2- बृक बँक की स्थापना हेतु भारत सरकार के आदेश संख्या: 8-2/2005, एम0सी0, दिनांक 11.04.2005 के अनुसार मदरसा जहाँ के लिए योजना स्वीकृत की जा रही है, रु. 7000/- प्रति मदरसा की एक मुश्त धनराशि अनुमत्त होगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी की निरीक्षण/पर्यवेक्षण आख्या जनवरी 2007 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। ताकि समयान्तर्गत उक्त सूचनायें भारत सरकार को उपलब्ध करायी जा सकें।

- 4- उक्त आर्बिट्रल धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त प्रतिक्रिया बजट में अनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्ण स्वीकृत आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृत प्राप्त करके ही किया जाय।
- 5- मिलव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय।
- 6- अप्रत्यक्ष धनराशि बजट में अनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय-साधियों के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 7- व्यय धनराशि के बी0एम0-8 निर्धारित विधि तक शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- 8- उक्त सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ-00-800-अन्य व्यय-05-अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण(100 प्रतिशत को0स10)-00-की मानक मद 20-सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामों द्वारा जायगा।
- 9- यह आदेश वित्त विभाग के अध्यासकीय संख्या: 1574/वित्त-3/2006, दिनांक 24 दिसम्बर 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)

अपर सचिव।

संख्या: 34 (1)/XVII(1)-03/06-62(स0क0)/2003./तद्विनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, वल्लारिखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, वल्लारिखण्ड, देहरादून।
- 3- सचिव, शिक्षा, वल्लारिखण्ड शासन।
- 4- विभागाधिकारी, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एवं नैनीताल।
- 5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, वल्लारिखण्ड, देहरादून।
- 6- निदेशक शिक्षा, वल्लारिखण्ड, देहरादून।
- 7- कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
- 8- वित्त अनुभाग-3, वल्लारिखण्ड शासन, देहरादून।
- 9- बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, वल्लारिखण्ड सचिवालय परिसर, 8 नियोजन विभाग, वल्लारिखण्ड, देहरादून।
- 10- उपनिदेशक(एम0सी0) मानव संसाधन विकास मंत्रालय(अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक: एक 8-2/2005-एम0सी0, दिनांक 4-8-2006 के कम में।
- 11- समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, वल्लारिखण्ड, देहरादून।
- 12- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र वल्लारिखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 13- विभागाधिकारी उधमसिंहनगर तथा हरिद्वार।
- 14- विभागाधिकारी वल्लारिखण्ड, हरिद्वार तथा उधमसिंहनगर।
- 15- गाई फाईल/विभागीय आदेश प्रतिक्रिया।

(धरेंद्र सिंह दलाल)
उपसचिव।

010207003